

## भारत में महाभियोग प्रक्रिया और न्यायिक जवाबदेही

### प्रलिस के लयः

[अनुच्छेद 124\(4\)](#), [अनुच्छेद 218](#), [न्यायाधीश जाँच अधनियम 1968](#), [बंगलुरु न्यायिक आचरण के सदिधांत 2002](#), [न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनरस्थापन 1997](#), [सरवोच्च न्यायालय](#), [उच्च न्यायालय](#), [संसद](#)

### मेन्स के लयः

[भारत में न्यायिक जवाबदेही](#), [न्यायाधीशों के लयि नैतिक मानक](#), [न्यायपालिका की सवतंत्रता और जवाबदेही](#)

[स्रोतः इंडयिन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक धार्मिक संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में [वविदास्पद टपिणी](#) के बाद [इलाहाबाद उच्च न्यायालय](#) के एक वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ [महाभियोग प्रस्ताव](#) पर वचार कया जा रहा है। कई लोगों द्वारा सांप्रदायिक भावना से प्रेरित मानी गई इन टपिणियों ने न्यायिक औचित्य और नष्पकषता पर चतिएँ उत्पन्न कर दी हैं।

### भारत में न्यायाधीशों के लयि महाभियोग प्रक्रया क्या है?

#### परचयः

- यदयपि [संवधान](#) में महाभियोग का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकनि बोलचाल की भाषा में यह उस प्रक्रया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कसिी न्यायाधीश को [संसद](#) द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।
- भारत में न्यायाधीशों के लयि महाभियोग प्रक्रया न्यायपालिका की सवतंत्रता को संरक्षति करते हुए [न्यायिक जवाबदेही](#) को बनाए रखने के लयि एक महत्त्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है।

#### संवधानिक सुरक्षा उपाय और महाभियोग के आधारः

- [अनुच्छेद 124\(4\)](#): यह अनुच्छेद सरवोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रया को रेखांकित करता है, जो [अनुच्छेद 218](#) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। महाभियोग के आधार स्पष्ट रूप से “[सदिध कदाचार](#)” और “[अक्षमता](#)” तक सीमति है।
  - [सदिध कदाचार](#): न्यायाधीश द्वारा कया गया ऐसा कृत्य या आचरण जो न्यायपालिका के [नैतिक और व्यावसायिक मानकों](#) का उल्लंघन करता है।
  - [अक्षमता](#): शारीरिक या मानसिक [अक्षमता](#) के कारण न्यायिक कर्तव्यों का पालन करने में न्यायाधीश की असमर्थता।

#### महाभियोग प्रक्रया के चरणः

- [प्रस्ताव की शुरुआत](#):
  - महाभियोग प्रस्ताव को [लोकसभा](#) में कम से कम **100 सदस्यों** या [राज्यसभा](#) में **50 सदस्यों** का समर्थन प्राप्त होना चाहयि।
  - प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का नरिणय लेने से पहले [अध्यक्ष](#) या [सभापति](#) प्रासंगिक वषिय की समीक्षा कर सकते हैं तथा वयक्तियों से परामर्श कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लयि, वर्ष 2018 में मुख्य न्यायाधीश दीपक मशिरा के खिलाफ प्रस्ताव को उचित वचार-वमिर्श के बाद [खारजि कर दया गया था](#)।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कयिह प्रक्रया लापरवाही से या नरिवाचिति प्रतनिधियों के महत्त्वपूर्ण समर्थन के बनिा शुरु नहीं की जा सकती।
- [जाँच समति का गठन](#):
  - प्रस्ताव स्वीकार होने पर, लोकसभा [अध्यक्ष](#) या राज्यसभा के सभापति एक **तीन सदस्यीय समति** गठित करते हैं, जिसमें नमिनलखिति शामिल होते हैं:
    - भारत के मुख्य न्यायाधीश या सरवोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
    - कसिी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

- एक प्रतष्ठिति वधिवित्ता
- समतिआरोपों की गहन जाँच करती है, **साक्ष्य एकत्र करती है** और आरोपों की वैधता नरिधारति करने के लयि गवाहों की जाँच करती है ।
- **समति की रपिर्त और संसदीय बहस:**
  - समति अपने नषिर्ष सदन के **पीठासीन अधिकारी** को सौंपती है, जहाँ प्रस्ताव पेश कयि गया था । यद न्यायाधीश कथति कदाचार या अक्षमता का दोषी पाया जाता है, तो रपिर्त पर संसद में बहस होती है ।
  - संसद के दोनों सदनों को **वशिष बहुमत** से प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी, जसके लयि नमिनलखिति की आवश्यकता होगी:
    - सदन की कुल सदस्यता का बहुमत ।
    - उपस्थति एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तहिई सदस्य ।
- **राष्ट्रपतिद्वारा अंतिम रूप से हटाना:**
  - एक बार दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर उसे उसी सत्र में **राष्ट्रपति** के समक्ष प्रस्तुत कयि जाता है ।
- **नयितरण और संतुलन:**
  - **महाभयिग के लयि समय सीमा:** महाभयिग प्रस्ताव को आरंभ करने और अनुमोदति करने से संबंधति कठोर प्रक्रयिओं से इसकेदुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है ।
  - **वशिषज्जों द्वारा वस्तुनषिठ जाँच:** जाँच समति में न्यायकि तथा वधिकि वशिषज्जों को शामिल करने से **नषिर्ष जाँच** सुनश्चिति होती है ।
  - **संसदीय नगिरानी:** संसद के दोनों सदनों को शामिल करने से इस प्रक्रयि में **जवाबदेहति** सुनश्चिति होती है ।
- **महाभयिग के प्रयासों के उदाहरण:**
  - भारत में महाभयिग के कुछ प्रयास हुए हैं जनिमें **न्यायमूर्तिवी. रामास्वामी (1993)** तथा **न्यायमूर्ति सौमतिर सेन (2011)** से संबंधति उल्लेखनीय मामले शामिल हैं ।
    - हालांकि इनमें से कसि भी न्यायाधीश को पूरी तरह से हटया नहीं जा सका । ये उदाहरण इस प्रक्रयि की कठोरता एवं जवाबदेहति बनाए रखने में इसकी भूमकि पर प्रकाश डालते हैं ।

## न्यायाधीशों के सार्वजनकि वक्तव्यों को कौन से दशिा-नरिदेश वनियमति करते हैं?

- **जमिंदारी के साथ अभवियक्ति की स्वतंत्रता: न्यायाधीश, सभी नागरकिों की तरह** संवधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभवियक्ति की स्वतंत्रता के हकदार हैं । हालांकि, यह अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता एवं उनके कार्यालय की अखंडता को बनाए रखने के क्रम में उचित प्रतबंधों के अधीन है ।
  - न्यायाधीशों के सार्वजनकि वक्तव्यों में कसि भी प्रकार के पूर्वाग्रह या पक्षपात का आभास नहीं होना चाहयि तथा यह सुनश्चिति होना चाहयि कवि अपने न्यायकि पद की गरमि बनाए रखें ।
- **बंगलुरु न्यायकि आचरण सदिधांत (2002)**
- **न्यायकि जीवन के मूल्यों का पुनरस्थापन (1997)**
- **न्यायकि आचरण हेतु आंतरकि तंत्र:** न्यायपालकि के पास ऐसे मामलों से नपिटने हेतु आंतरकि प्रोटोकॉल हैं जनिमें न्यायाधीशों के सार्वजनकि वक्तव्यों को अनुचित या वविदास्पद माना जा सकता है ।
- **न्यायकि संयम पर वशिषिट दशिानरिदेश:**
  - **राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करना:** न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कवि पक्षपातपूर्ण न समझे जाने के क्रम में राजनीतिक घटनाओं या नीतयिों पर टपिपणी करने से बचें ।
  - **मामलों में पूर्वाग्रह से बचना:** न्यायाधीशों को चल रहे मामलों या वधिकि मुद्दों के बारे में ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहयि जिन्हें पूर्वाग्रह या पक्षपात के रूप में समझा जा सकता है ।
  - **वविदास्पद घटनाओं में भागीदारी न करना:** न्यायाधीशों को ऐसे आयोजनों या मंचों में भाग लेने से बचना चाहयि जससे उनकी स्वतंत्रता से समझौता होता हो ।
- **सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणयिों:**
  - **???????????????? (2017)** में न्यायालय ने न्यायपालकि की अखंडता को कमजोर करने वाले एक न्यायाधीश के सार्वजनकि वक्तव्यों से होने वाले नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला ।
- **दशिानरिदेशों के कार्यानवयन संबंधी चुनौतयिों:**
  - **संहतिबद्ध नयिों का अभाव:** न्यायकि व्यवहार के कुछ पहलू (जैसे सार्वजनकि वक्तव्य) वैधानकि वनियमों के बजाय परंपराओं पर नरिभर हैं ।
  - **अभवियक्ति की स्वतंत्रता के तहत ग्रे एरयिा:** न्यायाधीश के अभवियक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार एवं न्यायकि मर्यादा बनाए रखने के उत्तरदायतिव के बीच संतुलन, अक्सर **व्यक्तपिरक** होता है ।

## वविधितापूर्ण समाज में न्यायपालकिा, नषिर्षता को कसि प्रकार बनाए रख सकती है?

- **संवधानकि मूल्यों का पालन करना:** न्यायपालकिा के मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में कार्य करने वाले संवधान में नहिति **समानता, न्याय एवं पंथनरिषेक्षता** जैसे सदिधांतों को महत्त्व देना चाहयि ।
  - न्यायाधीशों को इन सदिधांतों की व्याख्या एवं इनका अनुप्रयोग बना कसि पूर्वाग्रह या पक्षपात के करना चाहयि ।
- **न्यायपालकिा में प्रतनिधितिव सुनश्चिति करना:**
  - **समावेशी भरती:** यह सुनश्चिति करना कवि विभिन्न पृष्ठभूमयिों से आने वाले न्यायाधीशों, जनिमें **अल्प-प्रतनिधितिव** वाले समुदाय भी शामिल हैं, को न्यायपीठ में नयुक्त कयि जाए ।

- **लैंगिक संतुलन:** कानूनी व्याख्या में लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिये न्यायपालिका में **महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व** को प्रोत्साहित करना ।
- **हाशिये पर पड़े समुदायों के प्रति जागरूकता:** न्यायाधीशों को **अल्पसंख्यकों** और हाशिये पर पड़े समुदायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिये **प्रशिक्षित किया जाना चाहिये** ।
- **न्यायाधीशों की शक्ति और संवेदनशीलता:**
  - **विविधता और समता पर प्रशिक्षण:** न्यायिक अकादमियों को नयिमति रूप से **सांस्कृतिक क्षमता**, अंतरनहित पूर्वाग्रह और सामाजिक विविधता के प्रति संवेदनशीलता पर कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये ।
  - **ऐतहासिक असमानताओं के प्रति जागरूकता:** न्यायाधीशों को समाज में **वर्तमान प्रणालीगत असमानताओं को** समझना चाहिये तथा यह भी समझना चाहिये कि ये असमानताएँ किस प्रकार व्यक्तियों की न्याय तक पहुँच को प्रभावित करती हैं ।
- **वस्तुनिष्ठ नरिणय लेना:**
  - **न्यायिक नरिणय** केवल तथ्यों, साक्ष्यों और नरिधारित कानूनों पर आधारित होने चाहिये, तथा इसमें शामिल पक्षकारों की पहचान का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये ।
  - **न्यायाधीशों को सुविचारित नरिणय देने चाहिये**, जो उनकी तटस्थता और वधि के शासन के प्रतिपालन को प्रदर्शित करते हों ।
- **न्यायपालिका में प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को संबोधित करना:**
  - **पूर्व उदाहरणों की समीक्षा:** न्यायालयों को अतीत के नरिणयों की समालोचनात्मक **जाँच करनी चाहिये** ताकि उन उदाहरणों की पहचान की जा सके, जससे उनका समाधान किया जा सके, जहाँ पूर्वाग्रहों ने नरिणयों को प्रभावित किया हो ।
  - **कानूनों की न्यायसंगत व्याख्या:** न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कानूनों को इस प्रकार लागू किया जाए, जससे **समता और न्याय को बढ़ावा मिले**, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिये ।
- **कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा हेतु सक्रिय उपाय:**
  - **सामाजिक न्यायपीठ:** विशेष पीठ, जैसे कि वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित पीठ, हाशिये पर पड़े समुदायों को **प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है** ।
  - **वधिक सहायता और निःशुल्क सेवाएँ:** आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये **वधिक सहायता** सुनिश्चित करने से समावेशिता और नष्पक्षता में वृद्धि होती है ।
- **नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका:**
  - एक जागरूक **नागरिक समाज** और **सतर्क मीडिया** के नगरानीकर्त्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं, कि न्यायिक नष्पक्षता बनी रहे ।
  - न्यायिक कार्यों की **रचनात्मक आलोचना और जाँच**, स्वतंत्रता से समझौता किये बगैर **जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सहायता करती है** ।

## नष्पक्ष

भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में न्यायपालिका के लिये नष्पक्षता और जनता का विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है । विवादास्पद आचरण के उदाहरण न्यायिक जवाबदेही को स्वतंत्रता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं । न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखने और न्याय एवं समानता के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिये मज़बूत महाभियोग तंत्र, संवैधानिक मूल्यों का पालन और प्रशिक्षण एवं समावेशी प्रतिनिधित्व जैसे सक्रिय उपाय आवश्यक हैं ।

### दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

**प्रश्न:** न्यायपालिका की विश्वसनीयता और नष्पक्षता को बनाए रखने के लिये न्यायिक जवाबदेही आवश्यक है, विशेष रूप से भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में । टिप्पणी कीजिये ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

**[?/?/?/?/?]**

**प्रश्न 1.** भारत में जनहति याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिये । इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? (2024)

**प्रश्न 2.** विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये । (2021)

**प्रश्न 3.** भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नयुक्तिके संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये । (2017)

